खाद्यान्नों पर राज सहायता

@2079. **डा. जितेन्द्र कुमार जैन :**
श्री राम जेठमलानी :
श्री रामदास अग्रवाल :

क्या **खाद्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत तीन वर्षों से सरकार द्वारा खाद्यान्नों पर दी जाने वाली राज सहायता की राशि में निरन्तर वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1990-91 तथा वर्ष 1992-93 के दौरान दी गई राज सहायता की राशि कितनी थी;

(ग) क्या यह भी सच है कि इस अवधि के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से आम उपभोक्ताओं को बेचे जाने वाले गेहूं, चावल, चीनी की कीमतों में भी वृद्धि की गई है;

(घ) यदि हां, तो वर्ष 1991-92 तथा वर्ष 1992-93 के दौरान इन वस्तुओं की कीमतें कितनी-कितनी थीं;

(ङ) क्या यह भी सच है कि गेहूं और चावल का बिक्री मूल्य इनके वसूली मूल्य की तुलना में काफी अधिक था;

(च) यदि हां, तो इन वर्षों के दौरान वसूली मूल्य की तुलना में बिक्री मूल्य में कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई; और

(छ) राजसहायता की राशि में निरन्तर वृद्धि के क्या कारण हैं ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्प नाथ राय) : (क) और (ख) 1990-91, 1991-92 और 1992-93 के वर्षों के दौरान सरकार द्वारा भारतीय खाद्य निगम को खाद्य राज सहायता के प्रति निम्नलिखित राशियां अदा/निर्मुक्त की गई थीं :—

वर्ष	राज सहायता की राशि (करोड़ रुपयों में)
1990-91	2450*
1991-92	2850
1992-93	2800*

*. चीनी सहित

@पूर्वतः अतारांकित प्रश्न 1458, 10-5-93 से स्थानान्तरित।

(ग) और (घ) यद्यपि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए आम उपभोक्ताओं को बेचे जाने वाले गेहूं और चावल के खुदरा निर्गम मूल्य संबंधित राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों के प्रशासनों द्वारा स्वयं निर्धारित किए जाते हैं, लेकिन 1991-92 और 1992-93 के वर्षों के दौरान लेवी चीनी के खुदरा निर्गम मूल्य 24-7-1991 तक 525 रुपये प्रति क्विंटल, 20-1-92 तक 610 रुपये प्रति क्विंटल, 16-2-93 तक 690 रुपये प्रति क्विंटल थे और 17-2-1993 से यह मूल्य 830 रुपये प्रति क्विंटल है ।

(ङ) और (च) 1990-91 से 1992-93 के वर्षों के दौरान गेहूं और धान के वसूली/समर्थन मूल्यों और गेहूं और चावल के केन्द्रीय निर्गम मूल्यों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है । (नीचे देखिए)

(छ) खाद्य राज सहायता में वृद्धि मुख्यतया अनाज की वसूली लागत में वृद्धि होने, अभिवृद्धि लागत का आंशिक भार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के उपभोक्ताओं पर डालने, ब्याज प्रभारों में वृद्धि होने, भाड़ा दरों में वृद्धि होने, वेतन वृद्धि होने आदि के कारण ही हुई है ।

विवरण

1990-91 से 1992-93 के वर्षों के दौरान गेहूं और धान की वसूली/समर्थन मूल्यों और गेहूं और चावल के निर्गम मूल्य

(क) वसूली/समर्थन मूल्य — विपणन वर्ष — चावल : अक्तूबर-सितम्बर; गेहूं : अप्रैल-मार्च

(रुपये प्रति क्विंटल)

विपणन वर्ष	साधारण	बढ़िया	उत्तम	गेहूं
1990-91	205	215	225	215
1991-92	230	240	250	225
1992-93	270	280	290	250

(ख) केन्द्रीय निर्गम मूल्य (भारतीय खाद्य निगम के गोदाम से)	निम्न तारीख से प्रभावी	(रुपये प्रति क्विंटल) साधारण	बढ़िया	उत्तम
(क) चावल	24-6-1990 तक	244	304	325
	25-6-1990 से	289	349	370
	28-12-1991 से	377	437	458
	11-1-1993 से	437	497	518
(ख) गेहूं	30-4-1990 तक	204		
	1-5-1990 से	234		
	28-12-1991 से	280		
	11-1-1993 से	330		

Export of Rice by FCI

2080. SHRI P. UPENDRA : Will the Minister of FOOD be pleased to state :

(a) whether the Food Corporation of India has undertaken series of export deals for rice to various countries during the past three years ;

(b) whether demand of Indian rice in Sri Lanka, Mauritius and Europe has increased ;

(c) if so, the details of such export deals executed so for either by Food Corporation of India or by its various other agencies ;

(d) what steps have been taken to ensure remunerative price for Indian rice ; and

(e) if so, the details thereof ?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF FOOD (SHRI KALP NATH RAI) : (a) to (c) Food Corporation of India has not undertaken any export deal of rice to any country during the last three years. However, a small quantity of rice was supplied to Nepal and Cuba.

(d) and (e) Ministry of Commerce has fixed minimum export price for both basmati and non-basmati rice. No exports by private trade can, therefore, take place on F.O.B. Prices less than the minimum support prices. This ensures a remunerative price for the Indian rice which is being exported.

Committee on National Food Policy

2081. SHRI SATISH PRADHAN : Will the Minister of FOOD be pleased to state :

(a) whether Government have received the report from the Committee headed by Tamil Nadu Civil Supply Minister to formulate National Food Policy ;

(b) if so, what are the main features of the said report ; and